



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257614
CG-DL-E-01102024-257614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946

No. 276]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

मामला संख्या- एडी (ओआई) - 19/2024

विषय: चीन जन. गण. और रूस में उत्पन्न या निर्यात किए गए "पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई)" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/21/2024-डीजीटीआर—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और क्षति के निर्धारण के लिए पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे

इसके बाद "नियम" या "पाटनरोधी नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और रूस (जिसे इसके बाद "विषय देशों" के रूप में संदर्भित) में उद्भूत या वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन (पीटीएफई) (जिसे इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. और रूस से संबंधित वस्तुओं के पाटन किए गए आयात से भौतिक क्षति हो रही है और भौतिक क्षति का खतरा है और उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन (पीटीएफई) है। पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में उसकी अनूठी विशेषताओं जैसे रासायनिक जड़ता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण के कम गुणांक, नॉनटॉक्सिक, नॉनज्वलमेबल, विकिरण के प्रतिरोध, स्थैतिक और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और उत्कृष्ट विद्युत गुणों के लिए किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद को उप-शीर्ष 39046100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. आवेदक ने दायर आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

क्र.सं.	प्राचल	नींव	पूरा नाम
i. 1.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	जलीय फैलाव पीटीएफई
ii. 2.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	भरा हुआ यौगिक पीटीएफई
iii. 3.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पीटीएफई
iv. 4.	पीटीएफई	पीटीएफई	दानेदार पीटीएफई (सस्पेंशन ग्रेड)
v. 5.	पीटी- पीटीएफई	पीटी- पीटीएफई	दानेदार संशोधित पीटीएफई (मोल्टिंग ग्रेड / लो फ्लो वर्जिन ग्रेड / फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)

6. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषयगत देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और चीन जन.गण. और रूस से आयातित वस्तु विषयगत वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। विषयगत वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता विषयगत वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तु को चीन जन.गण. और रूस से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. विषय देश

8. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण. और रूस हैं।

घ. जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023- 31 मार्च 2024 (12 महीने) से है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण समान वस्तु या घरेलू उत्पादक हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, उस दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

11. यह आवेदन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने दायर किया है। आवेदक ने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही आवेदक किसी निर्यातक या विषय वस्तुओं के आयातक से संबंधित है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में संबंधित वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड है, जिसके पास संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है। तथापि, इससे नगण्य मात्रा प्राप्त हुई है जिससे आवेदक भारत में संबंधित वस्तुओं का वास्तविक एकमात्र उत्पादक बन गया है।

12. उपलब्ध जानकारी के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन पाटन रोधी नियमों के नियम 5 (3) के तहत खड़े होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) का हवाला दिया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार चीन जनसंपर्क अनुपात में उत्पादकों को यह प्रदशत करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदशत नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी सूचना बाजार द्वारा दी गई है तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से भारत में आयात पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि विषयगत वस्तुओं में विभिन्न ग्रेड शामिल हैं और इन ग्रेडों के आयात मात्रा में महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार, यूरोपीय संघ से कीमतों को इस स्तर पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित आधार नहीं माना जाता है। जांच के दौरान दावे की आगे जांच की जाएगी।

15. अतः प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ समायोजित करने के पश्चात उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार विषयगत वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ख. रूस के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा रूस के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित

लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

ग. निर्यात मूल्य

17. निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम डाटा के अनुसार भारत में आयातों के लिए सूचित सीआईएफ मूल्य पर विचार किया गया है। महासागर माल दुलाई, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए निवल निर्यात मूल्यों के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

घ. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर है और विचाराधीन देशों से निर्यातित उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विषय देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. संबंधित देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। विषय देशों से विषय वस्तुओं की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। विषय देशों से कम कीमत सकारात्मक है। विषय आयातों की उतराई तक की कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा। आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण बाजार हिस्सेदारी, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका कार्य-निष्पादन खराब हो गया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबंधित देशों से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान होने का खतरा है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे वास्तविक क्षति के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

20. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए, प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम

दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में विज्ञापन नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. जानकारी प्रस्तुत करना

23. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- -adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।
24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।
25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य पक्षों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. इच्छुक पक्षों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए www.dgtr.gov.in डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से डीजीटीआर (<https://dgtr.gov.in>) की वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

ताकि वे विषय जांच में आगे के विकास से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें। यह सुनिश्चित करेगा कि विषय जांच के लिए सभी इच्छुक पक्ष विषय जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adv13-dgtr@gov.in , consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय निवेदन करने या सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को एक साथ एडी नियमों के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार हो सकती हैं।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।

32. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

33. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से गोपनीय और/या अन्य जानकारी है जिसे

ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए संक्षेपण संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
35. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।
36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
37. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता के दावे पर अच्छे कारण के बयान के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय

के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझी जाती हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30 th September, 2024

Case No. AD(OI)-19/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene (PTFE)” originating in or exported from China PR and Russia.

- 1. F. No. 6/21/2024-DGTR**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s. Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene (PTFE)” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as “subject countries”).
2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR and Russia are causing material injury and threat of material injury and has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present application is Polytetrafluoroethylene (PTFE). The PUC is primarily used in the electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics such as chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, nonflammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.
4. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 39046100. The customs classification is indicative only and not binding on the

scope of the product under consideration.

5. The applicant has proposed the following product control numbers (PCNs), in the application filed:

S.No.	Parameter	Base	Full Name
i.	A-PTFE	A-PTFE	Aqueous Dispersion PTFE
ii.	C-PTFE	C-PTFE	Filled Compound PTFE
iii.	D-PTFE	D-PTFE	Fine Powder PTFE
iv.	PTFE	PTFE	Granular PTFE (Suspension Grade)
v.	PT-PTFE	PT-PTFE	Granular Modified PTFE (Molding Grade / Low Flow Virgin Grade/Free Flow Virgin Grade)

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and proposed PCNs, if any, within 15 days of date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from China PR and Russia are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as “like article” to the product being imported from China PR and Russia.

C. SUBJECT COUNTRIES

8. The subject countries for the present investigation are China PR and Russia.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

9. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st April 2023- 31st March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will include 1st April 2020-

31st March 2021, 1st April 2021-31st March 2022, 1st April 2022-31st March 2023, and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"Domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry "

11. The application has been filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. The applicant has not imported the subject goods from the subject countries nor is the applicant related to any exporter or importer of subject goods. The applicant has submitted that there is only one other producer of the subject goods in India, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which has capacity to produce the subject goods. However, the same has produced negligible quantities, making the applicant the de-facto sole producer of the subject goods in India.
12. On the basis of information available and after due examination, the Authority notes that production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production. Thus, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

(a) Normal Value for China PR

13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
14. The applicant has submitted that the imports into India from the EU is to be considered for the purpose of determining normal value. However, it is noted that the subject goods include various grades and the imports of these grades are not significant in volume. Thus, prices from EU is not considered as an appropriate basis for the determination of normal value for China at this stage. The claim shall be further investigated during the course of the investigation.
15. Therefore, the Authority has constructed normal value based on the best estimates of the cost of

the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits for the purpose of initiation.

(b) Normal Value for Russia

16. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available for Russia. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

(c) Export Price

17. The CIF price reported for imports into India, as per DG System data has been considered for the determination of export price. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses and bank charges. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

(d) Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. The volume of the subject goods from the subject countries has increased in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject countries is positive. The landed price of the subject imports had the depressing effect on the prices of the domestic industry. The applicant has claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, their performance has deteriorated in respect of market share, cash profit, profits and return on investment etc. The applicant has also claimed that there is a threat of injury to the domestic industry due to the dumped imports from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury and is facing threat of material injury due to dumped imports from the subject countries to justify the initiation of the anti-dumping investigation.
20. However, in order to examine the threat of material injury to the domestic industry, the Authority may seek post POI data from the applicant domestic industry and the other interested parties for examination.

H. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of Information

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses-adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://dgtr.gov.in>) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties

to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.

K. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses-adv13-dgtr@gov.in , consultant-dgtr@govcontractor.in , dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

30. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such

information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

39. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority